



अध्याय - प्रथम  
प्रस्तावना

प्रस्तावना

1-0 विषय प्रवेश

स्वतंत्र भारत ने सन् 1950 में भारतीय संविधान को स्वीकार करके भारत को गणराज्य घोषित किया। संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा राज्यों का विषय है। इसके अलावा शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार प्रकट किये गये। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को 10 वर्ष में (अर्थात् 1960 तक) अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। 46 वर्ष का लम्बा समय बीत जाने के पश्चात् भी आज तक हम प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य से बहुत दूर हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में प्रगति नहीं हुई है। बल्कि प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सुविधाओं अत्यधिक प्रसार हुआ है। देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो 1950-51 में लगभग 22 लाख थी, जो बढ़कर आज लगभग 632 लाख तक पहुँच गई है।

प्राथमिक शिक्षा किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला है। ओड (1973) ने प्राथमिक शिक्षा का महत्त्व बताते हुये कहा – "प्राथमिक शिक्षा किसी भी राष्ट्र की जीवन में प्राथमिक महत्त्व की वस्तु है। यह एक ऐसी सीढ़ी है, जिसे पार करके ही कोई राष्ट्र अपनी अभीष्ट सफलता प्राप्त कर सकता है।"

भारतीय शिक्षा आयोग (1966) ने शिक्षा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुये बताया – "शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हमें प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना होगा। अर्थात् 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का लक्ष्य की पूर्ति हम अभी तक नहीं कर सके हैं। देश के सभी इलाकों के सभी बच्चों की पाँच वर्ष तक की, अच्छी और प्रभावी शिक्षा की 1975-76 तक तथा 7 वर्ष की शिक्षा की

1985-86 तक व्यवस्था करने में समर्थ होना चाहिये ।" किंतु विभिन्न कारणों से यह लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सका ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति द्वारा यह घोषित किया गया कि 1990 तक इस आयु वर्ग के समस्त बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा । वह भी अभी तक पूरा नहीं किया जा सका ।

स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के इस व्यापक प्रसार के फलस्वरूप जिन शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है, वे गुणवत्ता में व्यापक भिन्नता लिए हुए हैं । गुणवत्ता की यह भिन्नता कुछ राज्यों, ग्रामीण एवं शहरी तथा शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में अधिक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है । गुणवत्ता की इस असंगत और असमान स्थिति के मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो बातों पर विशेष बल दिया गया -

- 1 विद्यालय की न्यूनतम भौतिक एवं अधिगम आवश्यकताओं की संपूर्ति ।
- 2 न्यूनतम अधिगम स्तर का निर्धारण ताकि सभी छात्र शैक्षिक मानक स्तर को प्राप्त कर सकें ।

न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम के मूल में शिक्षा में मौजूद विषमताओं को दूर करके गुणवत्ता को समता से जोड़ने की भावना है । एन सी ई आर टी के विद्यालय पूर्व एवं प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 1978 से "प्राथमिक शिक्षा पाठ्य चर्चा नवीकरण" कार्यक्रम के अंतर्गत इस दिशा में प्रयास करके प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम सातत्यक विकसित किए थे । राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 1986 में ऐसे "न्यूनतम अधिगम स्तरों" के निर्धारण पर बल दिया गया है, जिनकी संप्राप्ति प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने वाले सभी शिक्षार्थियों में आवश्यक रूप से होनी चाहिए । इस विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर पर एक दस्तावेज भी तैयार किया गया था ।

भारत सरकार के मानव ससाधन विकास मन्त्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा इस सबध मे गठित समिति की रिपोर्ट "प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर" फरवरी 1991 मे प्रकाशित हुई । साथ ही भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के अनुरूप न्यूनतम अधिगम स्तर कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे परिषद को भी भागीदार बनाया । परिषद मे एक कार्यदल का गठन किया गया जो विद्यालय पूर्व एव प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अतर्गत इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कार्यरत है ।

भारत सरकार ने "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना के द्वारा प्राथमिक कक्षाओ के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित कर गुणवत्ता सुधार के प्रयास भी किए है ।

## 1 1 न्यूनतम अधिगम स्तर

न्यूनतम अधिगम स्तरों के निर्धारण की आवश्यकता का उद्गम इस बुनियादी उद्देश्य से होता है कि एक समान स्तर की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, पथ, स्थान या लिंग के हो । न्यूनतम अधिगम स्तर सबधी कार्य की पृष्ठभूमि मे नीति निर्धारण का केन्द्र बिन्दु वर्तमान विषमताओं को दूर करना और समदृष्टि है । बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान मे रखते हुये गुणवत्ता को समता से जोडना है जो हमारे समाज के असुविधाग्रस्त तथा वचित वर्ग के है, बीच मे पढ़ाई छोड देते है, कहीं न कहीं काम कर रहे है और जिनमे लडकियाँ भी सम्मिलित है जो इस देश की विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग की जनसख्या का बडा भाग है और जिनकी निकट भविष्य मे सरचित शिक्षा के अतर्गत केवल प्राथमिक शिक्षा का ही अवसर मिल सकेगा । प्रत्येक शिक्षा स्तर की समाप्ति पर बच्चों को क्या सीख लेना चाहिए यह आधारभूत उद्देश्य न्यूनतम अधिगम स्तरों के निरूपण मे विशेष महत्व रखता है ।

अत्यंत सरल और सीधे शब्दों में यदि हम कहना चाहे तो कक्षा के प्रत्येक बच्चे को उस कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कम से कम उस मुकाम तक ले जाना, जो आवश्यक है और जिसकी अपेक्षा की गई है। अर्थात् यदि भाषा के पाठ्यक्रम में कक्षा 2 के लिए सरल वर्णनात्मक वाक्यों में अपने विचार व्यक्त करना निर्धारित है, तो कम से कम 80% बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम का 80% हर दशा में सीख ही जाना चाहिए। मोटे रूप में यही न्यूनतम अधिगम का स्तर होगा।

### 1 1 1 न्यूनतम अधिगम स्तर क्यों ?

समाज के हर व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के विषय में तो और भी बहुत कुछ कहा जाता है। छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने शिक्षा पूरी कर लेने पर भी व्यक्तित्व के अत्यान्वय गुणों की उस ऊँचाई को नहीं छू पाते हैं जो अपेक्षित एवं निर्धारित है। इसे ही हम शिक्षा में गुणवत्ता की कमी कहते हैं। गुणवत्ता की इस भीषण समस्या के समाधान के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण के साथ ही शिक्षक को उत्तरदायी ठहराकर प्रत्येक छात्र को उनकी संप्राप्ति भी सुनिश्चित की गई है।

### 1 1 2 न्यूनतम अधिगम स्तर की उपयोगिता

न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारण के अनेक लाभों में से प्रमुख है लक्ष्यों का स्पष्ट होना। दक्षताओं के रूप में बड़े स्पष्ट लक्ष्य शिक्षक के सम्मुख होंगे, इससे शिक्षकों को कार्य की एक नई दिशा मिलेगी और उनके सारे प्रयास निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तक ही केन्द्रित होंगे। सीखने विद्यार्थियों की प्रकृति में अधिगम

स्तर प्राप्त करने के प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शिक्षक दक्षता के अनुरूप अपनी विषय वस्तु और सिखाने की विधि निश्चित कर लेते हैं, और तदनुसार आवश्यक सहायक सामग्री जुटाकर व्यवहरचना कर सकते हैं। अधिगम स्तर निर्धारण से शिक्षको को इस कार्य में सरलता होगी। छात्रों में क्या-क्या और कितना सीखा है इसकी जाँच करने में भी अधिगम स्तर शिक्षको के लिए सहायक है। इसी से शिक्षक को जाँच के लिए प्रश्न निर्माण में दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। अर्थात् किसी एक दक्षता के मूल्यांकन में कौन सी विधि उपर्युक्त होगी, इसे अधिगम स्तर के आधार पर आसानी से सुनिश्चित किया जा सकता है। इससे छात्रों का वस्तुपरक मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। दक्षताये निर्धारित होने पर विषय वस्तु के चुनाव में शिक्षक स्वतंत्र है। पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु के छूट जाने अथवा अनचाही सामग्री जुड़ जाने की कोई संभावना नहीं रहती। यहाँ दक्षता की संप्राप्ति का महत्व है न कि पाठ्य पुस्तक को समाप्त करने का। किसी दक्षता को प्राप्त करने के बाद शिक्षार्थी उस दक्षता से संबंधित क्रियाओं को करने में सक्षम हो जाता है।

### 1 1 3 दक्षताओं का मूल्यांकन

न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित करने का लक्ष्य सभी विद्यार्थियों में उन सम्पूर्ण दक्षताओं का विकास करना है जो उसी स्तर अथवा कक्षा के लिए निर्धारित की गई हैं। मूल्यांकन वह आवश्यक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में विकसित दक्षता का पता लगाया जाता है। अभी तक की हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया केवल ज्ञान अवबोध और मानसिक कौशलों की जाच तक ही सीमित रहती है। अर्थात् केवल सज्ञानात्मक पक्ष का ही मूल्यांकन होता रहा है अतः हमें सज्ञानात्मक और असज्ञानात्मक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन करना चाहिए।

वर्तमान परीक्षा में कुछ चुने हुए अंशों पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे



मूल्यांकन की व्यापकता प्रभावित होती है। प्रचलित परीक्षा प्रणाली में मासिक—त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएँ ली जाती हैं। सीखने और मूल्यांकन का अंतराल बढ़ जाने से इनमें निरंतरता नहीं रहती और सही जांच नहीं हो पाती।

मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों में दक्षताओं के विकास की राह में कमियों का पता लगाना व इनको दूर करना होना चाहिए न कि वर्तमान में पास और फेल करना। मूल्यांकन सदैव औपचारिक ढंग से किया जाना चाहिए। यद्यपि न्यूनतम अधिगम स्तर में प्रस्तावित दक्षताओं का विकास सभी छात्रों में होना आवश्यक है।

#### 1 1.4 सप्रेषणीयता

न्यूनतम अधिगम स्तर में महत्वपूर्ण है कि उनको ऐसी भाषा व रूप में तैयार किया जाए जिससे वे सभी शिक्षकों के लिए सरलता से बोधगम्य हों, जब कि अनेक शिक्षक दूर के ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और बिना किसी बाहरी सहायता व मार्गदर्शन के अकेले कार्य करते हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर, प्राथमिक शिक्षकों के अतिरिक्त, अनौपचारिक शिक्षा, अभिभावकों और समुदाय के लिये भी बोधगम्य होना चाहिए। इस प्रकार यदि न्यूनतम अधिगम स्तरों से संप्राप्ति लक्ष्यों का काम लेना है तो उनको यथेष्ट सरल शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए जिससे वे उन सभी के लिए बोधगम्य हों, जिनका संबंध बच्चों के शैक्षणिक विकास से है।

#### 1 1.5 मूल्यांकनीयता

अधिकांश राज्यों में अनावरोधन या स्वतः कक्षागति की नीति का अनुसरण किया जाता है जिसके अनुसार बच्चों को पाठ्यक्रम को दोहराने के लिए एक ही कक्षा में नहीं रोका जाता, क्योंकि इसको बिना प्राथमिक स्तरीय शिक्षा भी पूरा

किए, बीच में ही विद्यालय छोड़ जाने का मुख्य कारण माना गया है । अनावरोधन (नो - डिटेन्शन) की नीति में यह मान लिया गया है कि सभी बच्चों में सीखने की एक योग्यता होती है बशर्ते उनको भली प्रकार पढ़ाया जाए । यह देखा जाता है कि कई शिक्षक 'अनावरोधन' का अर्थ "कोई परीक्षण नहीं" के रूप में लगाते हैं और छात्रों का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप, जब तक बच्चे प्राथमिक स्तर की अंतिम कक्षा में नहीं पहुँच जाते, प्रायः किसी को भी उनके सीखने की स्थिति का पता नहीं होता ।

न्यूनतम अधिगम स्तरों पर आधारित इन परीक्षणों के परिणाम ऐसे होने चाहिए जिनकी सहायता से शिक्षक, यह पहचान सकें कि किन अधिगम प्रतिफलों या दक्षताओं पर शिक्षार्थी ने पूर्ण दक्षता प्राप्त नहीं की है, कुछ न समझ में आने वाली इकाईयों का छात्रों को दुबारा सिखाया जाए और शिक्षक के लिए भी सुधार किया जा सके । इस प्रकार, न्यूनतम अधिगम स्तरों का सरलता पूर्वक मूल्यांकन योग्य शब्दों में उल्लेख करने में विद्यार्थियों को एक इकाई से दूसरी इकाई पर जाते समय पूर्ण दक्षता प्राप्त करने में सहायता मिलनी चाहिए ।

अतः न्यूनतम अधिगम स्तरों को इस प्रकार तैयार करने का प्रयास किया गया है कि शिक्षार्थी की उपलब्धियों का मूल्यांकन शिक्षक के लिए सरल हो जाए, चाहे वह लिखित परीक्षणों से किया जाए, चाहे मौखिक या अन्य प्रकार के परीक्षणों से ।

#### 1 1.6 प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य न्यूनतम अधिगम स्तर समिति (1990) के अनुसार

बच्चों को अक और चिन्हों की समस्याओं को शुद्धता व शीघ्रता से हल करने योग्य बनाना है जिनका उपयोग वे घर व बाजार में करते हैं । इस स्तर



पर गणित ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे पर्यावरण के क्षेत्र में स्थूल से सूक्ष्म तथा सामान्य से विशिष्ट की ओर जाकर बच्चों का ज्ञान अच्छा हो जाये । अतः न्यूनतम अधिगम स्तर समिति (1990) के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए -

- 1 शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता
- 2 मौखिक कथनों में -
  - अ समुचित चिन्हों का प्रयोग करते हुए गणितीय शैली में
  - ब रेखा चित्रों में रूपांतरित करने की योग्यता
- 3 काफी हद तक सही मापों का अनुमान एवं आकलन करने की योग्यता
- 4 दैनिक जीवन की साधारण समस्याएँ हल करने में गणितीय प्रत्ययों एवं कौशलों का प्रयोग करने की योग्यता
- 5 तार्किक ढंग से सोचने की योग्यता
- 6 क्रम एवं आकार पहचानने की योग्यता

प्रत्येक कक्षा के लिए आधारभूत गणितीय प्रत्ययों को शैक्षणिक क्रम के अनुसार सूचीबद्ध नहीं लिया गया है बल्कि उन्हें गणितीय दक्षताओं के निम्नलिखित पाँच क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है - (देखें परिशिष्ट)

### 1.1.9 अधिगम के संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक क्षेत्र

समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, न्यूनतम अधिगम स्तरों का निरूपण का प्रस्तुत कार्य पाठ्यचर्चा के निम्न क्षेत्रों तक सीमित है -

- भाषा
- गणित
- पर्यावरण अध्ययन (सामाजिक अध्ययन और विज्ञान) यद्यपि उक्त विषय

शारीरिक शिक्षा, कार्यानुभव और समीत एव कला शिक्षा को समग्र पाठ्यचर्या योजना से अलग नहीं किया जाना चाहिए । इसी प्रकार पाठ्यचर्या के असज्ञानात्मक पहलू अधिक नहीं तो, उतने ही महत्व के हैं जितने सज्ञानात्मक क्षेत्र । इतना ही नहीं असज्ञानात्मक अधिगम प्रतिफलों का सबध पाठ्यचर्या के उपर्युक्त विषयों में से एक से न होकर सभी से है, बल्कि उनके लिए, विद्यालय में और विद्यालय के बाहर अनेक प्रकार की पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन की भी आवश्यकता होती है । इनसे चरित्र का निर्माण होता है ।

### 1 1.8 प्राथमिक ऋणित के लिए तैयारी .

- 1 आकार, लम्बाई, मोटाई, भार और आयतन के आधार पर वस्तुओं को क्रम से रखना और उनके आपसी सबधों को उल्लेख करने के लिए विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना जैसे – से बड़ा, से छोटा, बराबर, से भारी, सबसे भारी आदि ।
- 2 विभिन्न गुणधर्मों जैसे – परिमाण, आकार, लम्बाई, आदि के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करना ।
- 3 किसी दिए गए बिन्दु से वस्तुओं एवं व्यक्तियों की दूरी की तुलना करना तथा उसके लिए पास, दूर सबसे निकट आदि शब्दावली का प्रयोग करना ।
- 4 आकार, रंग, स्थिति एवं परिमाण पर आधारित सरल नमूने देखना व उन्हें बनाना ।

न्यूनतम अधिगम स्तर एक नवीन सकल्पना है । अभी देश के विभिन्न विद्यालयों में स्थिति का आकलन भी आरम्भ किया जाना है । देश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा में श्रेष्ठ कार्य भी करते जायेंगे।



## 1 2 अध्ययन का महत्व

शोधकर्ता जिस शहरी क्षेत्र में अध्ययन कर रहा है वहाँ शासकीय प्राथमिक शाला में विभिन्न समुदायों के बालक-बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति क्या है यही जिज्ञासा प्रश्न शोध का आधार रही है। अतः समस्या को निम्न रूप से परिभाषित किया गया। सभी के प्रत्येक वर्ग की यह समस्या है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेने के बाद भी बालक बालिका ज्ञान, समझ, कौशल और व्यक्तित्व विकास के अन्य गुणों को नहीं सीख पाते वे अपेक्षित स्तर से काफी पीछे रह जाते हैं। प्रायः एक ही शहर अथवा स्कूल के छ के स्तर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है, जो कि एक महत्वपूर्ण समस्या है। राष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित मानदंड 80/80 का है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम सुविधाएँ ही छात्रों को उपलब्ध नहीं हैं। तो यह मानदंड संभव है।

## 1 3 संबंधित साहित्य का अध्ययन

गणित के क्षेत्र में किये गये कुछ प्रमुख शोध कार्य इस प्रकार हैं -

- राजपूत - 1984 - गणित विषय में उपलब्धि पर बुद्धि उपलब्धि अभिप्रेरण सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव।
- अग्रवाल - 1982 - विज्ञान एवं मानविकी विषय की छात्राओं पर उपलब्धि कर प्र चक्रवर्ती - 1988 - बुद्धि परिवार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तथा परिवार शैक्षणिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का समीक्षात्मक आ देशपाण्डे - 1986 - विद्यार्थियों पर बुद्धि तथा सामाजिक आर्थिक स्तर का छात्रों ग्रहकार्य तथा उपलब्धि पर अन्योन्य प्रभाव।

## 1 4 समस्या कथन

कक्षा पाँच के आदिवासी तथा गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित और असंज्ञान क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन।

## 1 5 शोध के उद्देश्य

उपर्युक्त शोध आकलन के पश्चात प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये –

- 1 आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर का अध्ययन ।
- 2 पहली पीढी के आदिवासी तथा गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन ।
- 3 दक्षताओं का विश्लेषण कर पाठ्य पुस्तक की चयनित इकाइयों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना ।
- 4 आदिवासी तथा गैर आदिवासी विद्यार्थियों के चयनित असज्ञानात्मक गुणों नियमितता औरसम्पन्ननिष्ठा ,कर्मठता ,सहकारिता और सत्यनिष्ठा का न्यूनतम अधिगम स्तर पर उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन ।
- 5 छात्रों के विभिन्न वर्गों (अभिभावक की शिक्षा एवं व्यवसाय ) का न्यूनतम अधिगम स्तर पर उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन।

## 1 6 शोध से संबंधित चर

लिंग छात्र, छात्राये

श्रेणी सामान्य, अनुसूचित जन जाति

स्वतंत्र चर छात्र छात्राये, सामान्य और अनुसूचित जन जाति

नियंत्रित चर आदिवासी क्षेत्र

आश्रित चर गणित की चयनित दक्षताये और असज्ञानात्मक उपलब्धि

## 1.7 शोध में प्रयुक्त चरों का अर्थ

### 1.7.1 आदिवासी क्षेत्र

मध्यप्रदेश के सदरभ में गिलिन और गिलिन के अनुसार –"स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी ऐसे समूह जो एक समान भाषा बोलता हो, एक समान संस्कृति का अनुसरण करता हो, और यह समूह किसी एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, वह आदिवासी क्षेत्र कहलाता है।"

### 1.7.2 प्राथमिक कक्षा

प्राथमिक स्तर का प्रयोग छात्रों के शैक्षिक सदरभ में किया गया है परंपरागत ढंग से शिक्षा की 4 कोटिया मानी जाती है, प्राथमिक 1 से 4 या 5, माध्यमिक 5 से 7 या 6 से 8, उच्चतर माध्यमिक 8 या 9 से 11 या 12 तक तथा महाविद्यालयीन उच्च शिक्षा/आधुनिक सदरभ में प्राथमिक शिक्षा के दायरे में कक्षा 7 या 8 तक के छात्र आ जाते हैं प्रशासनिक दृष्टि से यद्यपि विद्यालयों के नाम माध्यमिक विद्यालय हैं किंतु आधुनिक धारणा के अनुसार कक्षा 4 तथा कक्षा 6 दोनों के विद्यार्थी को प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी माना गया है।

### 1.7.3 न्यूनतम अधिगम स्तर

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट "प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर" फरवरी 1991 में प्रकाशित हुई जिसके अनुसार कक्षा के प्रत्येक छात्र को उस कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कम से कम उस मुकाम तक ले जाना जो आवश्यक है और जिसकी अपेक्षा की गई है। अर्थात् दक्षताओं के द्वारा कम से कम 80% बच्चों को निर्धारित पाठ्यक्रम का 80% हर दशा में सीख ही जाना चाहिए यही न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है।

## 1 8 शोध से संबंधित परिकल्पनाये

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध में शोध से संबंधित निम्न शून्य परिकल्पनाये है -

1 कक्षा पाच के आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित विषय में क्षेत्र - 1 (पूर्ण सख्याओ तथा अको का समझना) में न्यूनतम अधिगम स्तर में सार्थक अंतर नहीं है ।

1 1 आदिवासी समूह की छात्र और छात्राओ में क्षेत्र-1 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

1 2 गैर आदिवासी समूह की छात्र और छात्राओ में क्षेत्र-1 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

1 3 आदिवासी और गैर आदिवासी समूह के छात्रों में क्षेत्र-1 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

1 4 आदिवासी और गैर आदिवासी समूह की छात्राओ में क्षेत्र -1 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

2 कक्षा पाच के आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित विषय में क्षेत्र-2 (मूलभूत योग्यताओं) में न्यूनतम अधिगम स्तर में सार्थक अंतर नहीं है ।

2 1 आदिवासी समूह की छात्र और छात्राओं में क्षेत्र-2 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

2 2 गैर आदिवासी समूह की छात्र और छात्राओ में क्षेत्र-2 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।

- 2 3 आदिवासी और गैर आदिवासी समूह के छात्रों में क्षेत्र-2 में एम एल एल सार्थक अंतर नहीं है ।
- 2 4 आदिवासी और गैर आदिवासी समूह की छात्राओं में क्षेत्र-2 में एम एल एल में सार्थक अंतर नहीं है ।
- 3 कक्षा पाच के आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित विषय में क्षेत्र-3 (मुद्रा लबाई, भार, धारिता) में न्यूनतम अधिगम स्तर (एम एल एल ) में सार्थक अंतर नहीं है ।
- 4 कक्षा पाच के आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों के गणित विषय में क्षेत्र-4 (भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत) में न्यूनतम अधिगम स्तर में सार्थक अंतर नहीं है।
- 5 कक्षा पाच के आदिवासी और गैर आदिवासी विद्यार्थियों का असज्ञानात्मक क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर में सार्थक अंतर नहीं है ।

#### 1 9 न्यादर्श

न्यादर्श में कक्षा पाच के विद्यार्थियों में 33 सामान्य और 63 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी लिये गये हैं । जिसमें लगभग 30% छात्राएँ भी शामिल हैं ।

#### 1 10 अधिगम के असज्ञानात्मक क्षेत्र

अधिगम के अपेक्षित प्रतिफल केवल सज्ञानात्मक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखे जाना चाहिए बल्कि भावात्मक और मनोगत्यात्मक क्षेत्र के अपेक्षित अधिगम प्रतिफल के लिए असज्ञानात्मक क्षेत्र भी आवश्यक है । असज्ञानात्मक में व्यक्तित्व के ये तत्व अभिरूचियों, अभिवृत्तियों, व्यक्तित्व एवं सामाजिक व्यवहार और मूल्य व्यवस्था के रूप में प्रगट होते हैं।

प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बच्चे कुछ मूल्यों का विकास व अधिगम का प्रक्रिया के अग के रूप में अतर्ग्रहण करते हैं प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आयु लचीली होती है और उस समय उनको प्रदान किये गये अनुभव उनके व्यक्तित्व निर्माण पर अधिक स्थाई प्रभाव डाल सकते हैं ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देने की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है जैसे भारत की सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावादिता प्रजातंत्र एवं धर्म निरपेक्षता, स्त्री, पुरुष की समानता, पर्यावरण की सुरक्षा, सामाजिक दीवारों को दूर करना, लघु परिवार के आदर्श का पालन और वैज्ञानिक स्वभाव का सृजन ।

शिक्षा द्वारा "सामाजिक परिवेश जन्म सयोग द्वारा प्रसारित पूर्वाग्रहों एवं मनोग्रथियों को दूर कर सभी समान है, इसकी चेतना को जागृत किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त नीति निदेशक से मार्गदर्शन लेते हुए समिति यह सिफारिश करती है कि प्रत्येक विद्यालय को सभी बच्चों में कुछ आवश्यक गुणों का विकास करने के लिए व्यवस्थित प्रयास करना चाहिए, जिनसे बच्चों में व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में भी योगदान की भावना का विकास होता है । ये निम्न लिखित क्षेत्र इस प्रकार हैं -

- 1 नियमितता और समयनिष्ठा
- 2 स्वच्छता
- 3 अध्यवसायिता/कर्मठता
- 4 कर्तव्य और सेवा की भावना
- 5 समानता
- 6





- 7 उत्तरदायित्व की भावना
- 8 सत्यनिष्ठा
- 9 राष्ट्रीय तादत्म्य

इन क्षेत्रों में से शोधकर्ता द्वारा चार प्रमुख क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है निम्नलिखित है -

### 1 नियमितता और समयनिष्ठा

इन मूल्यों की अभिव्यक्ति, समय के मूल्य और समयबद्ध प्रतिबद्धता के प्रति सराहना तथा सवेदनशीलता के रूप में होती है। जीवन के हर क्षेत्र और प्रगति में इनका क्या महत्व है। यह सर्वविदित है। उदाहरण के लिए बच्चों को ऐसी आदत या जीवन शैली सीखनी होती है जिससे प्रतिदिन और समय पर विद्यालय जाने की नियमितता उनके स्वभाविक आचरण का एक अंग बन जाती है और वे किसी बाहरी अनुनय या दबाव से प्रभावित नहीं होते।

### 2 अध्यवसायिता/कर्मठता

इसका सबंध उन विशिष्ट आचरणों से उतना नहीं है जो बच्चों को करने चाहिए, जितना कि उस मूल्य से है जो वे परिश्रम व अध्यवसाय द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के साथ जोड़ते हैं। इस गुण के विकास से ही बच्चे लक्ष्योन्मुख कार्यों का उत्तरदायित्व लेने, उनको धैर्य के साथ कार्यान्वित करने और उनको समयबद्ध तरीके से सम्पन्न करने के लिए तैयार होते हैं।

### 3 सहकारिता

विद्यालय तथा विद्यालय से बाहर बच्चों को मिलकर रहने और काम करने के तपयक्त अवसर प्रदान कर जिन सभी में सामान्य लक्ष्य को मिलकर प्राप्त

करने के मूल्य का प्रादुर्भाव किया जाना चाहिए । बच्चे सहकारी प्रयासों की आवश्यकता को समझ सकें इसके लिए उनको स्थानीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मानव की स्वाभाविक परस्पर निर्भरता को समझाया जाना चाहिए । निस्संदेह यह कार्य सावधानी से किया जाना चाहिए । जिससे कि बच्चों की स्वनिर्भरता की भावना व्यष्टित्व तथा प्रतियोगिता की भावना पर जो समान रूप से महत्वपूर्ण है आच न आए ।

#### 4 सत्यनिष्ठा

अपने व्यवहार में काम के प्रत्येक पहलू में और जीवन में सत्यनिष्ठ रहने की आधारभूत प्रेरणा एक ऐसा गुण है जो प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए । बच्चे के व्यवहार के निर्धारण में इसका व्यापक महत्व है और यह उसके प्रत्येक आचरण पर वैधता व प्रमाणिकता की छाप लगाती है । यह अत्यावश्यक है कि बच्चों का विद्यालय में तथा घर पर उचित मार्गदर्शन किया जाए और उनकी इस बात में सहायता की जाए कि वे अपने विचारों तथा आचरण को इस कसौटी पर कसने की इच्छा शक्ति पैदा कर सकें ।

असंज्ञानात्मक क्षेत्र का सबध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यालय के प्रत्येक अधिगम अनुभव से है । यद्यपि इन गुणों के विकास की दृष्टि से विद्यालय का स्थान सर्वोपरि रहेगा तथापि परिवार और समुदाय भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं । वे इसमें बच्चों की यह सहायता करेंगे कि बच्चे इन गुणों का अन्तरीकरण कर उनको अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली का एक अंग बना लें । इस कारण से विद्यालय का असंज्ञानात्मक क्षेत्र से सबधित कार्य जटिल और कठिन हो जाता है ।

## 1 11 शोध की सीमाये

- 1 प्रस्तुत अध्ययन मे म प्र के शहडोल जिले के लगभग 50 आदिवासी और 50 गैर आदिवासी विद्यार्थियों को शामिल किया गया ।
- 2 इस अध्ययन मे प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5 के गणित विषय मे चार इकाईयो को शामिल किया गया है ।
- 3 न्यायदर्श मे छात्र व छात्राये दोनो को शामिल किया गया है ।
- 4 चार असज्ञानात्मक क्षेत्र -
  - 1 नियमितता ओर समय निष्ठा
  - 2 सहकारिता
  - 3 अध्यवसायिकता/कर्मठता
  - 4 सत्यनिष्ठा को शामिल किया है ।

### अध्ययन का महत्व

न्यूनतम अधिगम स्तर क्षेत्र मे कुछ अध्ययन अवश्य हुये है, किंतु वे पर्याप्त नही है । एक ओर जहा प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिर रहा है व न्यूनतम आवश्यक सुविधाये उपलब्ध नही हो पा रही है वही आदिवासी क्षेत्रो मे यह स्थिति ओर भी दयनीय है । इस आदिवासी क्षेत्र की प्राथमिक शालाओ के कक्षा 5 के छात्र छात्राओ की गणित के चयनित, दृष्ट-ताओ मे न्यूनतम अधिगम स्तर पर उपलब्धि ज्ञात कर, आने वाली कठिनाईयो को दूर करने के उद्देश्य से अध्ययन किया जा रहा है , जो कि काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है ।

इस अध्ययन से शिक्षा शास्त्री शिक्षक शोधकर्ताओ व बद्धिजीवियो को ध्यानाकर्षण

आदिवासी क्षेत्र की शैक्षिक समस्याओं की ओर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आदिम जाति विभाग के स्कूल के छात्र छात्राओं की उपलब्धि संबंधित कठिनाईयों एवं उनके निवारण की ओर सभी लोगों का ध्यानाकर्षित होगा ।

#### 1.12 उपकरण

सज्ञानात्मक उपलब्धि के लिए गणित की चयनित दक्षताओं के लिए प्रश्न पत्र (ग द प्र प ) बनाया तथा असज्ञानात्मक उपलब्धि के लिए असज्ञानात्मक के चयनित क्षेत्रों के लिए प्रश्नावली (अ क्षे प्र ) बनायी ।

\*